

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 767/2010/कोटा

मैसर्स फ़ैरो कंकरीट कन्सट्रक्शन (इण्डिया) प्रा.लि.

कोटा

अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

उडनदस्ता-वार्ड-द्वितीय, कोटा

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री विवेक सिंघल

अभिभाषक

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक: 14.12.2015

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, जयपुर के द्वारा 148/आर वैट/एनआरडी/07-08 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, वार्ड-द्वितीय, कोटा संभाग कोटा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) एवं 76 (12) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 08.12.2007 पारित करते हुए मांग राशि रु. 59,500/- आरोपित की, जिसको यथावत रखा गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 06.12.2007 को वाहन संख्या आरजे-26जी-1262 को चेक किया गया। वाहन में लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने मैसर्स न्यू चेतना गुड्स 310 कं. टों की जी आर नम्बर 4232 दिनांक 05.12.2007, मैसर्स फ़ैरो कन्सट्रक्शन (इण्डिया) प्रा.लि. इन्दौर का इश्यू एन्ट्री नम्बर-1, मैसर्स फ़ैरो कन्सट्रक्शन (इण्डिया) प्रा.लि. नॉट फार सेल अंकित पत्र एवं मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के तहत जारी फार्म 49 क 177910 दिनांक 24.10.2007 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि दस्तावेजों में टिन नम्बर अंकित नहीं हो एवं बिना वेट-47 के माल परिवहन करने के कारण मय वाहन कर वंचना के सन्देह में राज्य में हित में अधिनियम की धारा 76 (5)(ए) के तहत निरुद्ध किया जाकर नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 59,500/-आरोपित

की। उक्त शास्ति के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की है, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ वैट-49 संख्या 0122818 सम्पूर्ण विवरण भर कर प्रस्तुत किया गया था, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय राजस्थान राज्य बनाम डी पी मेटल्स (2001) 124 एस टी सी 611 के परिप्रेक्ष्य में नियमों की पालना मानी गयी है, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसको बाद की सोची हुई युक्ति मानकर अस्वीकार कर दिया गया। उनका कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय की व्याख्या अनुसार यदि वैट-49 संलग्न किये जाने की आवश्यकता भी है तो बिना छानबीन एवं जांच पडताल के तकनीकी कारणों पर बिना दोषी मनोभाव प्रमाणित किये शास्ति आरोपण करना अनुचित है। उनका कथन है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी का कोई दोषी मनोभाव नहीं होने से मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी व अन्य निर्णय दिनांक 3.5.2007 लागू नहीं होकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी.पी.मेटल्स (124 एसटी सी 611) लागू होता है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विधिक प्रावधानों एवं प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की है, जो अविधिक है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन संख्या 190/2012 मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाडी में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2013, एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन संख्या 3/2011 मैसर्स हीरामणी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ़ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बांसवाडा एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2013 को उद्धृत करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट-49 नहीं होने कारण कर निर्धारण अधिकारी नोटिस जारी किये जाने पर, उसकी पालना में अन्य घोषणा पत्र वैट-49 प्रस्तुत करना बाद की सोच (after thought) है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम



की धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत का 30 प्रतिशत शास्ति रु. 59,500/-आरोपित की गई है, जो उचित है। उन्होंने प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उद्धृत किये गये निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट-49 नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 59,500/-आरोपित की है, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2010 को पारित कर यथावत रखा है।

हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट-49 नम्बर 0122818 प्रस्तुत किया गया है, जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पेज 12 पर उपलब्ध है एवं वक्त चेकिंग माल के साथ घोषणा पत्र वैट-49 नहीं होने के कारणों को अपने जवाब में स्पष्ट किया है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति उचित नहीं है।

प्रकरण के तथ्यों से उजागर होता है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट-49 नहीं पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा वैट-49 नम्बर 0122818 प्रस्तुत कर दिया गया था। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स डी पी मेटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में शास्ति आरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखे जाने में अपीलीय अधिकारी ने विधिक त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उस सन्दर्भ में उद्धृत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट-2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case if it is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO,

who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

उपरोक्त सन्दर्भ में राजस्थान उच्च न्यायालय मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ़ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता बांसवाडा 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट-2 पेज 37 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

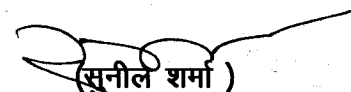
"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".....On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2010 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत ~~अपील~~ अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य